भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3060
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का संरेखण

†3060. श्री जयंत सिन्हा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और अन्वेषण प्रयासों को संरेखित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कदमों के कारण भारत को होने वाले संभावित लाभों का कोई विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का घरेलू अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता में कमी करने के उद्देश्य से अनेक नीतिगत पहलें की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति, खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी), वर्धित तेल निकासी (ईओआर) को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीति, कोयला खनन पट्टा के तहत क्षेत्रों से कोल बैड मीथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा तथा सीबीएम का शीघ्र मौद्रीकरण आदि जैसे सुधार शामिल हैं। अन्वेषण के अंतर्गत निवल भौगोलिक क्षेत्र को 2.5 लाख वर्ग कि.मी. (एसकेएम) से बढ़ाकर 5 लाख एसकेएम करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के 'नो-गो' क्षेत्र के 99 प्रतिशत क्षेत्र को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और विकास के लिए खोल दिया है। अभी तक ओएएलपी (बोली दौर VII तक) के तहत कुल 2,07,691 वर्ग कि.मी. तथा डीएसएफ (बोली दौर III तक) 16,508 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आबंटित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण संबंधी उपायों को बढ़ावा देने सहित बहुउद्देश्यीय कार्यनीति अपनाई है। इसने मांग प्रतिस्थापन, जैव ईंधनों/अन्य वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ईवी चार्जिंग सुविधाओं तथा आयातित कच्चे तेल पर देश की तेल निर्भरता में कमी करने के लिए रिफाइनरी प्रक्रिया सुधारों पर भी जोर दिया है।

*****